अध्याय 7

अंतरराष्ट्रीय व्यापार

वर्ष 2008 का वैश्विक आर्थिक संकट और इसके बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था में आई मंदी ने स्पष्ट रूप से दर्शाया है कि विश्व के एक कोने में पैदा होने वाला स्पंदन व्यापार चैनल के माध्यम से अन्यों के बीच दूसरे हिस्सों तक तेजी से पहुंच सकता है। वर्ष 2008 के वित्तीय संकट ने विश्व व्यापार (माल एवं सेवाएं दोनों) को वर्ष 2009 में 19.8% की एकदम नकारात्मक गिरावट के साथ झकझोर कर रख दिया था। इस वित्तीय संकट से पहले पांच वर्ष के लिए (2003-2007) विश्व व्यापार मूल्य 16.6% (मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर-सीएजीआर) की जबरदस्त वृद्धि के साथ बढ़ा और इस संकट के बाद के पांच वर्षों में यह 9.9% की मंद गति से बढ़ा। वैश्विक रूझान को देखते हुए, भारत के निर्यातों (माल एवं सेवाएं) में भी वित्तीय संकट के पूर्व के पांच वर्षों (2003-2007) में 30.1% की जबरदस्त वृद्धि हुई थी जिसके बाद वित्तीय संकट के बाद के पांच वर्षों (2009-2013) में 16.0% की मंद वृद्धि हुई। हालांकि अब इसकी संभावना बेहतर है, फिर भी विश्व और भारतीय व्यापार के लिए अभी भी स्थिति कमजोर बनी हुई है जिसमें 2008 के वित्तीय संकट के प्रघात अब भी दृष्टिगोचर हैं।

विश्व व्यापार

7.2 विश्व व्यापार के परिमाण की वृद्धि, जो वर्ष 2011 में 6.01% तक के पुनर्लाभ के पश्चात् वर्ष 2012 में घट कर 2.8% रह गई थी, ने हालांकि 3.0% की धीमी वृद्धि के साथ दोबारा पुनर्लाभ के संकेत दिए हैं। यहां भूमिकाएं बदलती प्रतीत हो रही हैं क्योंकि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं, जिनका व्यापार मोर्चे पर संकट के दुष्प्रभाव में निष्पादन खराब रहा था, ने उस उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) से बेहतर पुनर्लाभ के संकेत दिए हैं जो स्वयं भी एक न एक घरेलू संकट में उलझी हुई हैं। (सारणी 7.1)

(प्रतिशत परिवर्तन)

	वास्तविक		प्रेक्षण	
	2012	2013	2014	2015
विश्व व्यापार परिमाण (माल और सेवाएं)	2.8	3.0	4.3	5.3
आयात				
उन्नत अर्थव्यवस्थाएं	1.1	1.4	3.5	4.5
ईएमडीईज़	5.8	5.6	5.2	6.3
निर्यात				
उन्नत अर्थव्यवस्थाएं	2.1	2.3	4.2	4.8
ईएमडीईज़	4.2	4.4	5.0	6.2

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व इकॉनोमिक आऊटलुक, अप्रैल 2014

सारणी 7.1 : व्यापार परिमाणों में वृद्धि का रूझान

भारत का माल व्यापार

7.3 भारत का माल व्यापार वर्ष दर वर्ष महत्व में बढ़ता रहा है जिसमें वैश्विक निर्यात और आयात में इसका हिस्सा वर्ष 2000 में क्रमश% 0.7% और 0.8% से वर्ष 2013 में क्रमश% 1.7% और 2.5% तक, यद्यपि धीरे-धीरे बढ़ा है। विश्व में शीर्ष निर्यातकों और आयातकों में भारत की रैंकिंग विश्व व्यापार संगठन के अनुसार, निर्यात में वर्ष 2000 की 31वीं रैंक से सुधर कर वर्ष 2011 में 19वीं रैंक और उन्हीं वर्षों में आयात में 26वीं रैंक से सुधर कर 12वीं रैंक हो गई है। भारत के कुल माल व्यापार से जीडीपी अनुपात में भी वर्ष 2000-01 के 21.8% से वर्ष 2013-14 के 44.1% के रूप में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

भारत की निर्यात वृद्धि

7.4 विगत पांच वर्षों में, भारत की निर्यात वृद्धि में वर्ष 2008 के संकट के दुष्प्रभाव के रूप में 2009-10 में और यूरो क्षेत्र के आर्थिक संकट और वैश्विक मंदी के परिणाम के रूप में वर्ष 2012-13 में दो बार नकारात्मक दौर में होने के कारण काफी

उतार-चढ़ाव देखने में आया है। भारत का निर्यात वर्ष 2013-14 के दौरान 325 बिलियन अमरीकी डालर के लक्ष्य के मुकाबले 312.6 बिलियन अमरीकी डालर था, हालांकि पूर्व वर्ष के दौरान 1.8% की ऋणात्मक वृद्धि की तुलना में 4.1% की धनात्मक वृद्धि हुई है।

2012-13 में -1.8 प्रतिशत तक गिरावट के बाद 2013-14 में निर्यात वृद्धि में हल्की बहाली हुई।

7.5 वर्ष 2013-14 में मासिक निर्यात वृद्धि दरों में उतार-चढ़ाव रहा है। जुलाई से अक्तूबर 2013 तक चार महीनों के लिए निरंतर दो अंकों में रहने के बाद, ये नवंबर 2013 से जनवरी 2014 तक तीन महीनों के लिए घट कर एक अंकीय हो गई, अगले दो महीनों में ऋणात्मक दौर में रही और पूरे वर्ष के लिए 4.1% की धनात्मक परंतु निम्न वृद्धि पर रुकी। अप्रैल 2014 में, निर्यात वृद्धि 5.3% पर थोड़ी बेहतर थी और मई 2014 में 12.4% की वृद्धि के साथ छः महीने के अंतराल के बाद वापस दो अंकीय हो गई हालांकि यह निम्न आधार पर है।

व्यापार मात्रा और इकाई मूल्य

7.6 वर्ष 2012-13 में, जबकि अमरीकी डालर में निर्यात वृद्धि ऋणात्मक थी परंतु प्रमुखत% निर्यात के इकाई मूल्य की वृद्धि में 14.2 प्रतिशतता बिंदुओं की गिरावट के कारण रुपए के संबंध में यह वर्ष 2011-12 की 28.3% से घटकर वर्ष 2012-13 में 11.5% हो गई थी (सारणी 7.2)। निर्यात मात्रा वृद्धि में उपांतिक रूप से 1.0 प्रतिशतता बिंदुओं की गिरावट आई। निर्यातों की इकाई मूल्य वृद्धि में गिरावट क्रमशः रसायनों और संबंधित उत्पादों के निर्यातों की इकाई मूल्य वृद्धि में गिरावट तथा कुछ अन्य मदों जैसे कि खनिज ईंधनों, स्नेहकों और संबंधित सामग्री व विविध विनिर्मित वस्तुओं की इकाई मूल्य वृद्धि में गिरावट के कारण थी। निर्यातों की मात्रा वृद्धि में गिरावट मशीनरी और यातायात उपस्कर तथा प्रमुखतः पदार्थों द्वारा वर्गीकृत विनिर्मित वस्तुओं की वृद्धि में गिरावट के कारण थी।

7.7 आयातों के क्वांटम सूचकांक के वर्ष 2011-12 में ऋणात्मक 20.9% से सुधर कर वर्ष 2012-13 में धनात्मक 6.1% होने के बावजूद, आयातों के इकाई मूल्य में 66.9 प्रतिशतता बिंदुओं की उच्च गिरावट के कारण रुपये के संबंध में आयात भी पिछले वर्ष के 39.3% से घटकर वर्ष 2012-13 में 13.8% रह गया था। आयातों के इकाई मूल्य में उच्च गिरावट पेय पदार्थों व तंबाकू तथा विविध विनिर्मित वस्तुओं को छोड़कर लगभग सभी मदों के इकाई मूल्य में गिरावट के कारण थी, जबकि आयातों की मात्रा में थोड़ा सुधार रसायनों और संबंधित उत्पादों की मात्रा; मशीनरी व यातायात उपस्कर तथा विविध

आम धारणा के विपरीत, 2012-13 में मात्रा के रूप में पूंजीगत वस्तुओं के आयात में कोई गिरावट नहीं हुई।

सारणी 7.2 : व्यापार निष्पादनः मात्रा और इकाई मूल्य सूचकांक

(प्रतिशत में परिवर्तन)

	निर्यात				आयात				आयात-निर्यात स्थिति	
	रुपए में	अमरीकी डालर	परिमाण	यूनिट मूल्य	रुपए में	अमरीकी डालर	परिमाण	यूनिट मूल्य	निवल	आय
2001-02	2.7	-0.6	0.8	1.0	6.2	2.9	4.0	2.8	-2.1	-1.8
2002-03	22.1	20.3	19.0	2.9	21.2	19.4	5.8	14.3	-9.8	7.4
2003-04	15.0	21.1	7.3	7.5	20.8	27.3	17.4	3.1	3.6	11.2
2004-05	27.9	30.8	11.2	14.9	39.5	42.7	17.2	18.9	-3.5	7.3
2005-06	21.6	23.4	15.1	6.1	31.8	33.8	16.0	14.0	-6.0	8.2
2006-07	25.3	22.6	10.2	13.7	27.3	24.5	9.8	15.1	-1.3	8.8
2007-08	14.7	29.0	7.9	5.1	20.4	35.5	14.1	1.9	2.6	10.7
2008-09	28.2	13.6	9.0	16.9	35.8	20.7	20.2	13.8	2.5	11.7
2009-10	0.6	-3.5	-1.1	1.0	-0.8	-5.0	9.9	-10.0	12.3	11.1
2010-11	35.2	40.5	15.2	13.8	23.4	28.2	8.0	13.0	1.1	16.1
2011-12	28.3	21.8	8.9	20.2	39.3	32.3	-20.9	74.9	-31.5	-25.4
2012-13	11.5	-1.8	7.9	6.0	13.8	0.3	6.1	8.0	-1.6	6.3
2013-14	15.9	4.1	उ.न.	उ.न.	1.7	-8.3	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.

स्रोतः वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, (डीजीसीआईएण्डएस) कोलकाता के आंकड़ों से संगणित।
टिप्पणीः निर्यात एवं आयात की मात्रा एवं यूनिट मूल्य सूचकांक नए आधार (1999-2000=100) के साथ हैं।
उ.न. : उपलब्ध नहीं

विनिर्मित वस्तुओं में वृद्धि के कारण था। इस प्रकार, सामान्य धारणा के विपरीत, जहां तक मात्रा का संबंध है पूंजीगत वस्तुओं के आयात में कोई गिरावट नहीं थी। इसलिए पूंजीगत वस्तुओं के आयातों के मूल्य में गिरावट या तो पूंजीगत वस्तुओं की आयात कीमत में गिरावट के कारण या निम्न इकाई मूल्य की पूंजीगत वस्तुओं के आयात को अपनाने के कारण थी।

7.8 वर्ष 2012-13 में व्यापार की निवल वस्तु विनिमय के संबंध में वृद्धि, निर्यातों के इकाई मूल्य सूचकांक से आयातों के इकाई मूल्य सूचकांक का अनुपात, हालांकि अभी -16 प्रतिशत पर ऋणात्मक थी वह 2011-12 में -31.5 प्रतिशत की तुलना में सुधरा। यह 66.9 प्रतिशतता बिंदुओं तक आयातों की इकाई मूल्य सूचकांकों में उच्च गिरावट और 14.2 प्रतिशतता बिन्दुओं तक निर्यातों की इकाई मूल्य सूचकांक के अपेक्षाकृत न्यून गिरावट के कारण था। आयात की क्षमता को प्रतिबिंबित करते हुए व्यापार के रूप में आय व्यापार के रूप में निवल वस्तु विनिमय में सुधार के कारण 6.3 प्रतिशत और निर्यातों की मात्रा में 7.9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ सुधरा, जो 2011-12 में केवल एक प्रतिशतता बिन्दु तक गिरा।

निर्यात का निवल वस्तु-विनिमय और आय में 2011-12 की तुलना में 2012-13 में सुधार हुआ।

भारत और उभरती विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईडीई) का निर्यात निष्पादन

7.9 विश्व माल निर्यात में ईडीई का हिस्सा वर्ष 2000 में 25.4% से बढ़कर वर्ष 2012 में 42.3% हो गया है (सारणी 7.3)। इस बढ़ोतरी का लगभग 60% हिस्सा ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साऊथ अफ्रीका) देशों के लिए था जिनका हिस्सा 7.6% से बढ़कर 10.1% हो गया था। ब्रिक्स देशों में, सर्वाधिक बढ़ोतरी चीन के हिस्से में है, जिसके बाद रूस, भारत और ब्राजील का नंबर आता है। चार नई औद्योगिकीकृत एशियाई अर्थव्यवस्थाओं (एनआईएई) के हिस्से में 1 प्रतिशतता बिंदु की गिरावट आई है। यह प्रमुखत: ईडीई के अपेक्षाकृत उच्चतर सीएजीआर के कारण था जो 2000-10 के दौरान एनआईएई के 8.4% की तुलना में 13.9% पर था। यह वर्ष 1990 की स्थिति के बिल्कुल विपरीत है जब ईडीई की निर्यात वृद्धि एनआईएई की निर्यात वृद्धि से अधिक ऊंची थी।

1990 के दशक के विपरीत 2000 के दशक में ईकाई का निर्यात प्रदर्शन एनआईएई की तुलना में बेहतर था।

सारणी 7.3 : विश्व निर्यातों में निर्यात वृद्धि और हिस्सेदारी: भारत और चुनिंदा देश

	मूल्य (बिलियन अमरीकी डालर)	सीएजीआर		विकास दर (%)		विश्व निर्यात में हिस्सा (%)				हिस्से में परिवर्तन
	2012	1990-99	2000-12	2012	2013 (जनवरी-सितम्बर)	1990	2000	2012	2013 (जनवरी-सितम्बर)	2012/2000
ईडीई	7660	7.2	13.8	3.3	2.0	19.9	25.4	42.3	42.9	17.0
जिसमें							0.0			
चीन	2049	13.6	19.2	7.9	8.0	1.8	3.9	11.3	11.8	7.4
रूस	529	उन	14.4	1.4	-1.4	उन	1.7	2.9	2.8	1.3
मैक्सिको	371	14.4	6.9	6.1	2.1	1.2	2.6	2.1	2.1	-0.6
भारत	297	7.9	17.6	-2.0	4.7	0.5	0.7	1.6	1.7	1.0
मलेशिया	227	12.4	7.2	-0.3	-1.3	0.9	1.5	1.3	1.2	-0.3
ब्राजील	243	4.8	13.1	-5.3	-1.6	0.9	0.9	1.3	1.3	0.5
थाईलैंड	228	10.9	10.5	0.8	-1.0	0.7	1.1	1.3	1.2	0.2
इण्डोनेशिया	189	8.0	9.2	-6.0	-5.2	0.7	1.0	1.0	1.0	0.0
दक्षिण अफ्रीका	87	1.4	9.3	-9.9	-5.0	0.7	0.5	0.5	0.5	0.0
एनआईएईस	1700	8.4	8.2	-0.1	उन	7.7	10.4	9.4	उन	-1.0
कोरिया रिपब्लिक	548	9.2	10.1	-1.3	1.3	1.9	2.7	3.0	3.0	0.3
हांगकांग	443	8.7	6.8	3.3	3.3	2.4	3.2	2.4	2.5	-0.7
सिंगापुर	408	9.0	9.5	-0.3	-0.6	1.5	2.2	2.3	2.2	0.1
ताईवान	301	6.8	6.1	-2.3	उन	1.9	2.3	1.7	उन	-0.7
विश्व	18092	5.6	9.1	0.1	1.2	100.0	100.0	100.0	100.0	—

स्रोत: अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय सांख्यिकी, आईएमएफ जनवरी, 2014 से परिकलित।
नोट: एनए : उपलब्ध नहीं

7.10 वर्ष 2000 और 2010 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में व्यापार हिस्सों में एकदम परिवर्तन प्रमुखत% चीन के व्यापार के कारण था जिसमें 20.3% की उच्चतम वृद्धि दर देखी गई और जो तीन ब्रिक्स देशों–रूस, भारत और ब्राजील में निम्नतर सीमा तक रही। जबकि 2012 में, चीन और मैक्सिको को छोड़कर अधिकांश ईडीई और एनआईएई की वृद्धि दरें निम्न या ऋणात्मक रही, 2013 में (जनवरी-सितंबर) 8.0% के साथ केवल चीन और इसके बाद 5.0 के साथ भारत ने अच्छी वृद्धि पाई थी।

7.11 विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अनुसार, 2014 की प्रथम तिमाही में, यूरोपीय संघ और सिंगापुर को छोड़कर अन्य सभी बड़े देशों की निर्यात वृद्धि दरें ऋणात्मक रही जैसा कि चीन (-3.8%), हांगकांग (-1.8%), इंडोनेशिया (-1.8%), जापान (-3.9%), थाइलैंड (-1.0%), दक्षिण अफ्रीका (-4.2%) और रूस (-1.8%) के मामले में अथवा निम्न रही जैसा कि अमरीका (2.5%), मलेशिया (3.6%) और आस्ट्रेलिया (2.0%) के मामले में।

7.12 वर्ष 2014 की प्रथम तिमाही में आयात वृद्धि दरें भी इंडोनेशिया (-6.3%), मलेशिया (-1.5%), थाइलैंड (-15.4%) और आस्ट्रेलिया (-3.1%) में ऋणात्मक वृद्धि तथा अमरीका (2.0%), चीन (1.7%), और हांगकांग (1.0%) में निम्न वृद्धि के साथ वही तस्वीर प्रस्तुत करती हैं। केवल यूरोपियन संघ (5.2%), जापान (5.6%) और सिंगापुर (4.2%) की अपेक्षाकृत अच्छी वृद्धि दरें थी।

निर्यात संघटन और क्षेत्रवार निष्पादन

7.13 भारत के निर्यात बास्केट में वर्ष 2000-01 से 2013-14 के बीच सुस्पष्ट संघटनात्मक परिवर्तन हुए हैं जिसमें पैट्रोलियम, कच्चा तेल और उत्पादों की हिस्सेदारी लगभग पांच गुणा बढ़कर 20.1% तक हो गई जो कि इसकी 33.5% वृद्धि (सीएजीआर) द्वारा प्रक्षेपित हुई (सारणी 7.4)

सारणी 7.4 : भारत के निर्यातों का जिंस संघटन

	प्रतिशत हिस्सा		सीएजीआर	वृद्धि का प्रतिशत[क]
	2000-01	2013-14	2000-01 to 2012-13	2013-14
I प्राथमिक उत्पाद	16.0	15.6	16.9	4.7
(क) कृषि एवं संबद्ध उत्पाद	14.0	13.8	17.0	5.1
(ख) अयस्क एवं खनिज	2.0	1.8	16.5	1.4
II विनिर्मित वस्तुएं	78.8	63.7	15.1	4.6
(क) आरएमजी सहित वस्त्र	23.6	9.7	8.0	14.6
(ख) रत्न एवं आभूषण	16.6	13.1	15.9	-5.2
(ग) अभियांत्रिकी वस्तुएं	15.7	19.8	19.1	8.8
(घ) रसायन एवं संबंधित उत्पाद	10.4	13.2	19.5	5.9
(ड.) चमड़ा एवं चमड़ा उत्पादन	4.4	1.8	8.0	16.7
(च) हाथ से बने कालीन सहित हथकरघा	2.8	0.4	-0.3	10.9
III पेट्रोलियम, अपरिष्कृत एवं उत्पाद	4.2	20.1	33.5	3.0
कुल निर्यात	100.0	100.0	17.2	4.1

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस डाटा से परिकलित

टिप्पणी: [क]अमरीकी डालर के रूप में वृद्धि दर

7.14 जबकि यहां प्राथमिक उत्पादों के हिस्से में थोड़ी गिरावट रही हैं, विनिर्मित वस्तुओं के हिस्से में 15.1 प्रतिशत बिंदुओं की गिरावट थी। विनिर्मित वस्तुओं के अंतर्गत चार बड़ी मदों में रत्न और आभूषण तथा वस्त्र (आरएमजी सहित) के हिस्सों में गिरावट आई जिसमें परवर्ती मद में 9.7 प्रतिशत तक की यह गिरावट आधे से अधिक रही है। दो प्रमुख विनिर्मित वस्तु मदों, इंजीनियरिंग वस्तुओं और रसायनों और संबंधित उत्पादों की हिस्सेदारियों में उनकी लगभग 20% सीएजीआर होने के कारण वृद्धि हुई है। वर्ष

2000-01 से 2013-14 के बीच विनिर्मित वस्तुओं की निर्यात हिस्सेदारियों में गिरावट इन मदों की अमेरीका जैसे मुख्य गंतव्यों को निर्यात हिस्से में गिरावट के कारण है। इन मदों में, अमरीका को किए गए वस्त्रों और रत्न व आभूषणों के निर्यात के हिस्सों में गिरावट आई जबकि रसायनों व संबंधित मदों और इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यातों के हिस्सों में बढ़ोतरी हुई। यूरोपीय संघ के मामले में, वस्त्रों, इंजीनियरिंग वस्तुओं और रसायनों व संबंधित उत्पादों के हिस्सों में बढ़ोतरी हुई जबकि रत्न व आभूषणों तथा चमड़े के हिस्सों में गिरावट आई। चीन के मामले में, वस्त्रों और इंजीनियरिंग वस्तुओं के हिस्सों में बढ़ोतरी तथा रसायनों व संबंधित उत्पादों के हिस्से में गिरावट आई। इस प्रकार भारत के निर्यात में संघटनात्मक परिवर्तनों के साथ-साथ दिशात्मक परिवर्तन भी हो रहे हैं।

7.15 निर्यात् के हाल के क्षेत्रवार कामकाज (सारणी 7.5) से पता चला है कि जहां 2012-13 में कई क्षेत्रों में नकारात्मक विकास जोन में आते हैं वहीं 2013-14 में रत्नों, आभूषणों और इलेक्ट्रानिक सामानों को छोड़कर अन्य सभी बड़े क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि रही है। 2014-15 (अ॰) के प्रथम दो महीनों में इंजीनियरिंग सामानों (21.7 प्रतिशत), पेट्रोलियम उत्पादों (14.0 प्रतिशत) समुद्री उत्पादों (40.1 प्रतिशत) और वस्त्र (13.2 प्रतिशत) क्षेत्रों के कामकाज में और भी सुधार हुआ है।

7.16 निर्यात के क्षेत्रवार कामकाज की दिलचस्प बात यह है कि कई श्रमिक साध्य निर्यात क्षेत्रों ने वर्ष 2013-14 में बेहतर प्रदर्शन किया है। वर्ष 2013-14 में वस्त्र निर्यात में 14.6 प्रतिशत वृद्धि हुई है। भारत के कुल वस्त्र निर्यात में यूरोपीय युनियन और संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा आधा होता है और वर्ष 2013-14 में इन बाजारों में हमारा वस्त्र निर्यात क्रमश: 13.5 प्रतिशत और 7.0 प्रतिशत रहा है। एक दूसरी बात यह है कि चीन को किया जाने वाला भारतीय वस्त्रों का निर्यात बढ़ा है और इसमें चीन का हिस्सा 2010-11 के 2 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में 5 प्रतिशत हो गया जो और भी बढ़कर 2013-14 में 7 प्रतिशत तक पहुंच गया है। अन्य श्रमिक साध्य क्षेत्र जैसे कि चमड़ा और चमड़ा उत्पादों का निर्यात वृद्धि 16.7 प्रतिशत के ऊंचे स्तर पर रही है। 2013-14 में कुल चमड़ा निर्यात का लगभग 72 प्रतिशत यूरोपीय युनियन और संयुक्त राज्य अमरिका को दिया गया जिसमें क्रमश: 15.4 प्रतिशत और 27.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कार्पेट समेत हस्तशिल्प का निर्यात भी दो अंकों में अर्थात् 10.9 प्रतिशत तक पहुंच गया है जबकि 2013-14 में कुल निर्यात में इसका हिस्सा केवल 0.4 प्रतिशत ही था।

7.17 भारत के निर्यात क्षेत्र की एक प्रमुख बात बढ़ता हुआ विदेशी मूल्य संवर्द्धन और घटता हुआ घरेलू मूल्य संवर्द्धन है। सभी देशों और महाद्वीपों में उत्पादन प्रक्रिया का विखण्डन आर्थिक वैश्वीकरण का तेजी से प्रमुख विशेषता बनता जा रहा है। ऐसा विशेष कर भारत की अर्थव्यवस्था में देखने में आता है। ध्यान देने की बात है कि विभिन्न देशों में बाद के चरण या प्रक्रिया में मध्यवर्ती भागों या घटकों का उत्पादन किया जाता है और फिर बाद में उनका अन्य देशों को आगे के उत्पादन के लिए निर्यात कर दिया जाता है। उत्पादन प्रक्रिया के इस बढ़ते हुए विखडन के कारण विश्व व्यापार की न केवल विभिन्न अंतिम उत्पादों के बारे में विशेषज्ञता हासिल कर रहे देशों के मद्दे नजर विचार किया जाना चाहिए बल्कि इस पर उत्पादों के उत्पादन के विभिन्न घटकों या प्रक्रियाओं में विशेषज्ञता की भी दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए। व्यापार की भूमिका और घरेलू रोजगार और आय सृजन में व्यापार के अंशदान पर भी तदनुसार विचार किया जाना चाहिए (बॉक्स 7.1)।

वृद्धि	2012-13	2013-14(अ)
सकारात्मक	1. पेट्रोलियम उत्पाद 2. रसायन 3. कृषि एवं सहायक उत्पाद 4. चमड़ा एवं उत्पाद 5. समुद्री उत्पादे	1. पेट्रोलियम उत्पादे 2. इंजीनियरिंग सामान 3. रसायन 4. कृषि एवं सहायक उत्पाद 5. वस्त्र 6. चमड़ा एवं उत्पाद 7. समुद्री उत्पाद 8. अन्य एवं खनिज
नकारात्मक	1. इंजीनियरिंग सामान 2. रत्न एवं आभूषण 3. वस्त्र 4. इलेक्ट्रानिक सामान 5. अयस्क एवं खनिज	1. रत्न एवं आभूषण 2. इलेक्ट्रानिक सामान
सकल	-1.8	4.1

स्रोत: डीजीसीआईएण्डएस आंकड़ों पर आधारित
टिप्पणी: अ.=अनन्तिम

सारणी 7.5 : निर्यात के क्षेत्रवार कामकाज

कई श्रम साध्य निर्यात क्षेत्रों का 2013-14 में तुलनात्मक दृष्टि से कामकाज बेहतर रहा है।

भारत के आयात में वृद्धि

7.18 आयात वृद्धि में तेजी से गिरावट आयी है जो कि 2011-12 के 32.3 प्रतिशत से कम होकर 2012-13 में 0.3 प्रतिशत तक आ गया है और 2013-14 में इसमें 8.3 प्रतिशत की गिरावट आयी है। ऐसा इसलिए हुआ है कि गैर तेल आयात में 12.8 प्रतिशत की कमी आयी है। आयात के अन्य बड़े मदों पेट्रोलियम आयल और लुब्रीकेन्ट्स (पी॰ओ॰एल॰), जिनका 2013-14 के कुल निर्यात में 36.7 प्रतिशत का हिस्सा था, में 0.7 प्रतिशत की मामूली बढ़ोत्तरी हुई है। यह मामूली वृद्धि पीओएल

बॉक्स 7.1 : भारत के निर्यात में संवर्द्धित घरेलू मूल्य और विदेशी अवयव का आकलन

1995 से 2011 के दौरान भारत के निर्यात में आयात अवयव तेजी से बढ़कर 11 प्रतिशत से 22 प्रतिशत तक हो गया था। आयात अवयव (या विदेशी संवर्द्धित मूल्य) में तुलनात्मक रूप से व्यापारिक निर्यात में वृद्धि हुई है जो कि इसी अवधि के दौरान 11 प्रतिशत से बढ़कर 26 प्रतिशत (सारणी 1) हो गया है। एकक जिंस के स्तर पर निर्यात के आयात अवयव में सबसे ज्यादा वृद्धि जहाज और नौका (लगभग 60 प्रतिशत प्वायण्ट) में हुई है फिर उसके बाद पेट्रोलियम उत्पाद और उर्वरक (20 प्रतिशत प्वाइंट से अधिक) का स्थान है।

सारणी 1 : भारत के व्यापारिक और कुल निर्यात में घरेलू और विदेशी वर्धित मूल्य का हिस्सा

	हिस्सा	1995	1998	2000	2003	2005	2007	2009	2011
व्यापारिक निर्यात	घरेलू वर्धित मूल्य	88.83	87.78	84.34	82.94	75.96	74.62	72.74	74.28
	विदेशी वर्धित मूल्य	11.17	12.22	15.66	17.06	24.04	25.38	27.26	25.72
कुल निर्यात	घरेलू वर्धित मूल्य	89.49	88.4	85.32	85.26	79.81	78.57	76.61	78.02
	विदेशी वर्धित मूल्य	10.51	11.6	14.68	14.74	20.19	21.43	23.39	21.98

स्रोत: विश्व निवेश-निर्गत् डाटा बेस (डब्ल्यू आई ओ डी) के निवेश-निर्गत सारणी के आधार पर परिगणित।

हालांकि वर्ष 2008 में भारत के निर्यात में 24 प्रतिशत पर विदेशी वर्धित मूल्य का हिस्सा चीन के 33 प्रतिशत, मलेशिया और थाईलैण्ड के 38 प्रतिशत, फिलीपीन्स के 42 प्रतिशत, कोरिया के 43 प्रतिशत, वियतनाम के 46 प्रतिशत और ताईवान के 40 प्रतिशत से कम था। इस प्रकार विश्व मूल्यशृंखला में समेकन की मात्रा की दृष्टि से कई उदीयमान उत्तर-पूर्वी अर्थव्यवस्थाओं जैसे कि ताइवान, कोरिया, फिलीपीन्स, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैण्ड और चीन से बहुत पीछे है लेकिन दक्षिण अफ्रीका, इण्डोनेशिया और ब्राजील भारत से भी पीछे हैं। यद्यपि 1998 से 2007 की अवधि के दौरान सकल दृष्टि से निर्यात में वृद्धि हुई है फिर भी लगभग सभी असंगठित जिंसों के मामले में सकल निर्यात में घरेलू वर्धित मूल्य में गिरावट का रूख देखने में आया है। परम्परागत रूप से निर्यातोन्मुखी क्षेत्र जैसेकि वस्त्र, चमड़ा और चमड़ा उत्पाद, दवाइयों और औषधियों, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल और सहायक क्षेत्रों में कई वर्षों से घरेलू वर्धित मूल्य में गिरावट का रूख देखने में आया है। घरेलू वर्धित मूल्य सूती वस्त्रों में 5 प्रतिशत प्वायण्ट, रेडिमेड वस्त्रों में 4 प्रतिशत प्वायण्ट और दवाओं तथा औषधियों में 8 प्रतिशत प्वायण्ट की कमी आयी है। 1998 से 2011 के दौरान कुल निर्यात में घरेलू वर्धित मूल्य चीन और भारत के मामले में काफी कम अर्थात् 10 प्रतिशत प्वायण्ट तक कम हो गया है और ब्राजील के मामले में 4 प्रतिशत की मामूली गिरावट आयी है। इण्डोनेशिया के मामले में इसका विलोम रूख दिखाई दिया है जहां कि निर्यात में घरेलू वर्धित मूल्य में (6 प्रतिशत प्वायण्ट) की वृद्धि हुई है।

स्रोत: डॉ॰ देव कुमार दास के आईसीआरआईईआर, इस्टिमेटिंग डोमेस्टिक वॅल्यू एडेड एण्ड फारेन कन्टेन्ट्स ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट पर किए गए अध्ययन के आधार पर जिसको आर्थिक मामले का विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया था।

(2.6 प्रतिशत) में हुई साधारण मात्रा वृद्धि के कारण हुई है और ऐसा कच्चे तेल की कीमत उसके औसत कीमत से (इण्डियन बास्केट) से थोड़ा कम होने के बावजूद हुआ है जोकि 2012-13 के 108.0 अमेरिकी डॉलर/बीबीएल से कम होकर 2013-14 में 105.5 अमेरिकी डॉलर/बीबीएल हो गया है।

7.19 आयात का एक प्रमुख मद सोना है जिसका आयात 2011-12 के 1078 टन से कम होकर 2013-14 के 1037 टन हो गया था जो आगे और भी कम होकर 2013-14 में 664 टन तक आ गया था। यह सब कुछ तब हुआ जब सरकार ने कई उपाय किए थे। मूल्य की दृष्टि से सोने और चांदी के आयात में वर्ष 2013-14 में 40.1 प्रतिशत कम होकर 33.4 बिलियन अमेरिकी डालर तक हो गया था। पूंजीगत माल एक अन्य बड़ा आयात वर्ग है।

7.20 2012-13 और 2013-14 दोनों ही वर्षों में इनके आयात में क्रमश: 3.4 प्रतिशत और 14.7 प्रतिशत की कमी आयी है, जो कि एक चिंता का विषय है (सारणी 7.6)। पूंजीगत माल के मामले में इलेक्ट्रिकल और मशीन टूल्स को छोड़कर मशीनरी और परिवहन उपकरणों के आयात में वर्ष 2013-14 में 10 प्रतिशत से अधिक की कमी आयी है। हालांकि पूंजीगत माल के आयात की प्रमात्रा में वर्ष 2012-13 में वास्तव में वृद्धि हुई है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

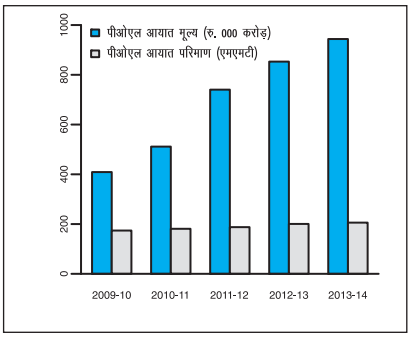

चित्र 7.1 : पीओएल आयात

सरकार द्वारा किए गए कई उपायों के कारण वर्ष 2013-14 में सोने के आयात में तेजी से कमी आयी है।

	जिन्स समूह	प्रतिशत हिस्सा 2000-01	प्रतिशत हिस्सा 2013-14	सीएजीआर 2000-01 से 2012-13	वृद्धि दर (प्रतिशत)[क] 2013-14
I.	**खाद्य एवं संबद्ध उत्पाद**	3.3	3.2	21.5	-15.9
	जिसमें से				
1	अनाज	0.0	0.0	16.0	3.8
2	दलहन	0.2	0.4	29.1	-25.5
3	खाद्य तेल	2.6	2.1	19.6	-16.9
II.	**ईंधन**	33.5	40.4	21.9	0.4
	जिसमें से				
4	पीओएल	31.3	36.7	21.6	0.7
III.	**उर्वरक**	**1.3**	**1.4**	**24.0**	**-28.0**
IV.	**पूंजीगत वस्तुएं**	10.5	11.9	23.0	-14.7
	जिसमें				
5	इलेक्ट्रिकल एवं मशीनी औजारों को छोड़कर	5.9	5.2	20.6	-14.5
6	इलेक्ट्रिकल मशीनरी	1.0	1.0	20.4	-2.0
7	परिवहन संबंधी उपकरण	1.4	3.3	30.6	-12.8
V.	**अन्य**	52.5	38.4	18.5	-14.4
	जिसमें से				
8	रसायन	5.9	5.7	19.2	4.3
9	मोती, कीमती पत्थर अर्द्ध कीमती पत्थर	9.7	5.3	13.7	5.7
10	सोना और चांदी	9.3	7.4	23.0	-40.1
11	इलेक्ट्रिक वस्तुएं	7.0	6.9	**20.0**	-1.5
	कुल आयात	**100.0**	**100.0**	**21.0**	**-8.3**

स्रोत: डीजीसीआई एण्ड एस डाटा से संगणित।
टिप्पणी: [क]अमरीकी डालर में वृद्धि दर।

2012-13 और 2013-14, दोनों ही वर्षों में पूंजीगत माल के आयात के मूल्य में तेजी से कमी आयी है।

सारणी 7.6 : भारत के आयातों की जिन्सवार संरचना

व्यापार घाटा

7.21 वर्ष 2013-14 में आयात में आई कमी और निर्यात वृद्धि के सामान्य रहने के कारण भारत के व्यापार घाटे में 27.8% की कमी आई है। निरपेक्ष रूप से देखें तो यह व्यापार घाटा वर्ष 2012-13 के दौरान 190.3 बिलियन अमेरिका डॉलर से कम होकर 137.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था। हालांकि पीओएल घाटे में कोई भी बदलाव नहीं आया जो कि पिछले दो सालों में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आस-पास लटक रहा था। सोने तथा पूंजीगत मात्रा दोनों के ही आयात में कमी आने के कारण गैर पीओएल घाटा 2012-13 के 87.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से तेजी से कम होकर 2013-14 में 35 बिलियन तक आ गया।

व्यापार घाटा

7.22 2013-14 में उत्तरी अमेरिका (9.1%) और अफ्रीका (7.2%) को किए जाने वाले निर्यात में अच्छी वृद्धि हुई थी। जबकि यूरोप (4%) और एशिया (1.7%) को किए जाने वाले निर्यात में वृद्धि धीमी रही। तथा लैटिन अमेरिका (-20%) और सीआईएस तथा बाल्टिक देशों (4.7%) को होने वाले निर्यात में नकारात्मक वृद्धि देखी गई है। जहां संयुक्त राज्य अमेरिका को होने वाले निर्यात में 8.3% की वृद्धि हुई थी वहीं ईयू 27 को होने वाले निर्यात में मात्र 2.2% की वृद्धि हुई है इसका कारण यह था कि यूरोपीय समुदाय से मंदी आ गई थी। संयुक्त अरब अमीरात में -16% की गिरावट आई। एशिया को किया जाने वाला निर्यात अभी भी भारत के निर्यात का लगभग 50% है। जहां एक ओर, आसियान (एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन्स) को किए जाने वाले भारत के निर्यात में 0.5% की मामूली वृद्धि हुई थी, वहीं दूसरी ओर दक्षिणी एशिया को किए जाने वाले निर्यात में काफी वृद्धि देखने में आई थी। यह निर्यात सार्क के चार देशों (साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रिजनल कॉरपोरेशन) अर्थात् श्री लंका, बंग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान साथ ही साथ भूटान को किया जा रहा था। चीन तथा जापान को किए जाने वाले निर्यात में भी क्रमश: 9.5% तथा 11.7% की अच्छी खासी वृद्धि हुई है। क्षेत्रवार सभी पांचों क्षेत्रों से होने वाला आयात में कमी आई है और सर्वाधिक कमी यूरोप से होने वाले आयात में हुई है जो कि -19.3% है।

दक्षिण ऐशिया को होने वाले भारत के निर्यात में अच्छी प्रगति रही और सार्क के प्रमुख देशों को होने वाले निर्यात में ऊंची वृद्धि दर रही है।

7.23 वर्ष 2013-14 में 58% पर भारत के व्यापार में इसके 15 शीर्षस्थ व्यापारिक भागीदारों का हिस्सा लगभग वही रहा है जो इसके पहले के वर्षों में रहा है। भारत के तीन शीषर्स्थ व्यापारिक भागीदार चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा संयुक्त अरब अमीरात हैं। जिनका स्थान आगे-पीछे होता रहा है। निर्यात-आयात अनुपात जिससे द्विपक्षीय व्यापार संतुलन से प्रकट होता है (सारणी 7.7), 2013-14 में अपने शीर्षस्थ 15 व्यापारिक भागीदारों ने चार देशों के साथ भारत की द्विपक्षीय व्यापार अतिरेक का है। यह देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर तथा हांगकांग। और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ रहने वाले निर्यात-आयात अनुपात में तेजी से वृद्धि हुई है। स्विटजरलैण्ड के साथ होने वाले व्यापार के द्विपक्षीय व्यापार घाटे में तेजी से कमी आई है जो कि 2012-13 के 31.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम होकर 2013-14 में 17.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक हो गया। ऐसा सोने के आयात में हुई कमी के कारण हुआ। भारत का चीन के साथ एक बहुत ही उच्च और बढ़ता हुआ द्विपक्षीय व्यापार संबंध है जो कि 2013-14 में गिरकर 6.6% रह गया है इन दोनों एशियाई देशों के बढ़ते महत्व को देखते हुए भारत को चीन के लिए एक व्यापक व्यापार रणनीति तैयार करनी चाहिए जिसमें चीन को निर्यात करने की भारतीय क्षमता पर विशेष ध्यान देना चाहिए (बॉक्स 7.2)।

सारणी 7.6 : प्रमुख व्यापार भागीदारों के साथ भारत का व्यापार-हिस्सा तथा आयात-निर्यात अनुपात

रैंक	देश	कुल व्यापार में हिस्सा				आयात-निर्यात अनुपात[क]			
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (अ)	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (अ)
1	चीन	9.50	9.15	8.32	8.63	0.36	0.33	0.26	0.29
2	यूएसए	7.30	7.31	7.76	8.06	1.26	1.49	1.43	1.76
3	यूएई	10.72	9.14	9.54	7.82	1.03	0.98	0.93	1.05
4	सऊदी अरब	4.04	4.75	5.53	6.39	0.23	0.18	0.29	0.33
5	स्विटजरलैंड	4.11	4.57	4.21	2.78	0.03	0.03	0.03	0.09
6	जर्मनी	3.00	2.95	2.73	2.66	0.57	0.51	0.51	0.59
7	हांगकांग	3.18	2.94	2.55	2.63	1.10	1.24	1.55	1.74
8	इण्डोनेशिया	2.52	2.71	2.55	2.60	0.57	0.45	0.36	0.33
9	ईराक	1.56	2.48	2.59	2.55	0.08	0.04	0.07	0.05
10	सिंगापुर	2.73	3.17	2.67	2.53	1.38	2.02	1.82	1.85
11	कुवैत	1.96	2.20	2.23	2.39	0.18	0.07	0.06	0.06
12	बेल्जियम	2.32	2.20	1.97	2.24	0.67	0.69	0.55	0.59
13	नाईजीरिया	2.08	2.20	1.87	2.23	0.19	0.18	0.23	0.19
14	कतार	1.16	1.73	2.07	2.19	0.06	0.06	0.04	0.06
15	कोरिया	2.29	2.16	2.19	2.18	0.36	0.34	0.32	0.34
	कुल शीर्षस्थ 15 देश	58.46	59.64	58.78	57.89	0.54	0.49	0.48	0.53
	कुल	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**0.68**	**0.63**	**0.61**	**0.69**

स्रोत: डीजीसीआई एण्ड डाटा से संगणित।

टिप्पणी : [क]0 से 1 के बीच आयात एवं निर्यात के सहगुणांक का मतलब यह है कि भारत का आयात निर्यात से अधिक है तथा एक से अधिक सहगुणांक का मतलब यह है कि भारत का निर्यात आयात से अधिक है।

बॉक्स 7.2 : भारत से चीन को निर्यात की संभावना

2013-14 में भारत से चीन को किए जाने वाला व्यापार 2000-01 में 2.3 बिलियन डॉलर से बढ़कर 68.9 बिलियन हो गया। चीन का भारत में कुल व्यापार वर्ष 2000-01 में 2.5% था जो कि 2013-14 में बढ़कर 8.6 हो गया। तथा भारत का चीन में कुल व्यापार 2001 की तुलना में 0.7 से बढ़कर 2013 में 1.6 हो गया। भारत का चीन में आयात सीएजीआर में 31.2 प्रतिशत बढ़ गया जो कि चीन से निर्यात के सीएजीआर के 24.9% की तुलना में अधिक था।

तथापि, भारत का चीन को होने वाला निर्यात, चीन को कुल आयात (लगभग 1% हिस्सा) में एक छोटा ही अनुपात है, 2008 में भारत के कुल द्विपक्षीय निर्यात की संभावना 28.4 बिलियन डॉलर आंकी गई थी जिसके 2012 (तालिका 1) में बढ़कर 53.4 बिलियन होने की संभावना थी। वर्ष 2013-14 में भारत से चीन को किया जाने वाला वास्तविक निर्यात 14.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। 2008 में, चीन के वास्तविक द्विपक्षीय निर्यात में भारत की निर्यात संभावना लगभग तीन गुना थी और आगे 2012 में 'साढे तीन गुना बढ़ गई जिसका कारण 2012 में चीन में भारत के निर्यात में कमी आना था। चीन एक बहुत महत्वपूर्ण बाजार है जहां पर भारत की निर्यात संभावना का पर्याप्त रूप से प्रयोग नहीं किया जा रहा है। भारत की व्यापक व्यापार संभावना को चीनी बाजार के विविध क्षेत्रों में प्राथमिक तथा श्रम-साध्य उत्पाद से तकनीक आधारित उपायों के विभिन्न स्तरों तक अब व्यवस्थित किया जाना चाहिए।

जारी...

बॉक्स 7.2 : भारत से चीन को निर्यात की संभावना (जारी...)

सारणी 1 : चीन को निर्यात की संभावना : 2004-12 के दौरान प्रमुख मद

खण्ड	मदों का विवरण	निर्यात संभावना 2012 में (मिलियन अमेरीका डालर)	अनुपात			सीएजीआर
			2004	2007	2012	2008-12
5	खनिज पदार्थ	19520	7.6	9.7	36.6	14.9
16	मशीनरी तथा तकनीकी उपकरण	13828	43.2	55.9	25.9	-3.8
6	रसायन उत्पाद	3952	9.1	5.8	7.4	11.1
17	वाहन, वायुयान तथा पोत	3391	5.4	4.3	6.4	16.7
7	प्लास्टिक तथा इसके पदार्थ	2647	7	5.4	5	9.7
18	नेत्र, फोटोग्राफ तथा सिनेमेटोग्राफी	2385	6	4.5	4.5	12.3
15	बेस मेटल तथा इसके उत्पाद	2352	7.8	7	4.4	2.8
11	वस्त्र तथा वस्त्र उत्पाद	1493	4.9	2.3	2.8	18.6
	कुल निर्यात	53357	100	100	100	6.9

स्रोत: लेखक का अनुमान श्रम कामरेड, ऑनलाइन एक्सेस्ड ऑन 25 अक्तूबर, 2013 पर आधारित है।
नोट: आंकलित की गई निर्यात संभावना 'मोडीफाइड ट्रेड क्रिएटिंग इफेक्ट' वाइनर मॉडल का विस्तार पर आधारित है। द्विपक्षीय व्यापार का प्रवाह का प्रयोग करते हुए 6 अंकों के मद पर आंकलित किया गया है।

चीन को किये जाने वाली प्रमुख संभावित वस्तुओं में खनिज उत्पादों के अतिरिक्त मशीनरी तथा यांत्रिक उपकरण तथा रसायन8 के उत्पाद हैं जिसमें भारत के द्विपक्षीय निर्यात की लगभग 1/3 संभावना निहित है। भारत को निर्यात की संभावना मुख्य रूप से कुछ क्षेत्रों में केंद्रित है जिसमें मध्यावधि में लगभग 90.2% के लिए7 प्रमुख क्षेत्र उत्तरदायी हैं जिसमें से अधिकतर विनिर्माण क्षेत्र से सम्बन्धित हैं। एक व्यापक इंडो-चाइना व्यापार रणनिति जो कि भारत के घरेलू चिंताओं के मुद्दों जैसे कि सस्ती चाइना वस्तुओं को डम्प करना, के बारे में ध्यान देती है को पारस्परिक रूप से फायदेमंद बनाया जा सकता है।

स्रोत: डॉ एस॰के॰ मोहन्ती (2013) द्वारा किए गए अध्ययन 'एक्सामिनिंग डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडियास एक्सपोर्ट टू डेवलपिंग कन्ट्रोल इन ए ग्लोबल इकॉनामी पार्टली अफेक्टेड बाय रिसेसशन, जिसका प्रायोजन भारत सरकार आर्थिक कार्य मंत्रालय ने किया था, पर आधारित है।

भारत का सेवा व्यापार

7.24 वाणिज्यिक सेवा व्यापार में, भारत वर्ष 2012 में वैश्विक निर्यात में 3.4% हिस्सेदारी के साथ छठे बड़े निर्यातक के स्थान पर रहा तथा वैश्विक आयात में 3.0% हिस्सेदारी के साथ, सातवें बड़े आयातक के स्थान पर रहा। पांच वर्षों में 2008 से पहले (2003-04 से 2007-08) सेवा निर्यात वृद्धि (सीएजीआर) 35.4% तीव्र थी तथा उपरोक्त तरीके से, वाणिज्यिक निर्यात वृद्धि 25.8% थी। पांच वर्ष के पिछले संकट में (2008-09 से 2012-13) सेवा निर्यात वृद्धि, जो 8.3 प्रतिशत थी व्यापार निर्यात वृद्धि के 12.8% से कम थी। 2012-13 में 145.7 अमेरिकी डॉलर का सेवा निर्यात 2.4% की न्यून वृद्धि को दर्शाता है जो कि पिछले वर्ष 14.2% की तुलना में अत्यधिक कम थी। इसमें 2013-14 में 4% वृद्धि के साथ थोड़ा सा सुधार हुआ, (सारणी 7.8) व्यापारिक वाणिज्यिक वृद्धि

वस्तु समूह	हिस्सा (प्रतिशत)		सीएजीआर 2002-03	विकास दर	
	2002-03	2013-14	to 2013-14	2012-13	2013-14
यात्रा	16.0	11.8	16.6	-2.5	-0.4
परिवहन	12.2	11.5	19.1	-5.0	0.3
बीमा	1.8	1.4	17.2	-15.4	-4.8
जीएनआईई	1.4	0.3	4.8	20.1	-14.9
विविध	68.6	75.0	20.8	4.9	5.6
साफ्टवेयर सेवाएं	46.2	45.8	19.7	5.9	5.4
गैर साफ्टवेयर सेवाएं	22.4	29.1	22.7	3.4	5.9
जिसका:					
व्यवसाय सेवाएं	3.9	18.8	38.3	9.8	0.1
वित्तीय सेवाएं	3.3	4.4	23.1	-17.1	34.4
संचार सेवाएं	3.9	1.6	10.4	5.4	43.0
कुल सेवा निर्यात	100.0	100.0	19.8	2.4	4.0

सारणी 7.7 : भारत का सेवा निर्यात

स्रोत: आरबीआई डाटा पर आधारित
टिप्पणी: जीएनआईई=सरकार अन्यत्र शामिल नहीं

भी इसी प्रकार रही। तथापि 45.8 प्रतिशत हिस्सा सोफ्टवेयर सेवाओं का तथा 29.1 प्रतिशत हिस्सा गैर सोफ्टवेयर का रहा है और इसमें क्रमशः 5.4% तथा 5.9% की वृद्धि हुई अन्य सभी प्रमुख वर्गों में बहुत ही कम या नकारात्मक वृद्धि हुई।

7.25 अन्य सभी प्रमुख वर्गों ने सेवा आयात जो कि 2012-13 में थोड़ा सा 3.2 बढ़ा 2013-14 में घटकर 2.8 हो गया, नकारात्मक वृद्धि दर्ज की। हाल के वर्षों में भारत के बढ़ते व्यापार घाटे के वित्तीयन में निवल सेवाएं एक प्रमुख स्रोत रही हैं। वर्ष 2006-07 से 2012-13 के दौरान कुल मिलाकर वाणिज्यिक व्यापार घाटे का लगभग 38% का वित्त पोषण हुआ। जहां 2012-13 में निवल सेवाओं में वाणिज्यिक व्यापार घाटे का 33.2% वित्त पोषण हुआ वहीं 2013-14 के दौरान सेवा आयातों में गिरावट तथा सेवा निर्यात में मंदी के साथ निवल सेवाओं ने वाणिज्यिक व्यापार के 49.4% तक वित्तीयन किया।

व्यापार घाटा भारतीय परिप्रेक्ष्य

7.26 व्यापार घाटा व्यापार का एक महत्वपूर्ण तत्व है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अध्ययन के अनुसार व्यापार घाटे में एक प्रतिशत की वृद्धि के परिणामस्वरूप उस देश के वास्तविक आयात में 0.4% की वृद्धि होती है।

7.27 मार्च 2014 के अन्त तक, भारत में लघु-अवधि व्यापार घाटे (1 वर्ष तक) का कुल अन्तर्वाह 6.02400 तक पहुंच चुका था जो कि साल-दर-साल 9.7 की अवनति को प्रदर्शित करता है। 100.2 बिलीयन अमेरिका डॉलर के आधार पर वर्ष 2013-14 में अर्न्तवाही व्यापार घाटा 2012-13 की तुलना में 18.4% कम था जबकि व्यापार घाटे के बहिर्वाह में वृद्धि 4.0% थी। जिसके परिणाम स्वरूप 2012-13 में 21.7 बिलियन अमेरिकी डालर के निवल अन्तर्वाह की तुलना में 2013-14 में व्यापार घाटे के तहत 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था का निवल निकास हुआ था।

7.28 वर्ष 2012 में न्यून वृद्धि के पश्चात्, व्यापार घाटा 2012-13 में बढ़कर 14.2% हो गया। 2013-14 में यह कम होकर 10.5% हो गया। निवल बैंक के प्रतिशत के रूप में निर्यात ऋण, जो कि पिछले वर्षों में लगातार कम होता रहा है, 23 मार्च 2001 की स्थिति के अनुसार लगभग 9% से अधिक से था 21 मार्च 2014 को गिरकर 3.8% रह गया (सारणी 7.9)। सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्यातकों को व्यापार ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाने के लिए कई कदम उठाए है। (बॉक्स 7.3)

तिथि को बकाया	निर्यात ऋण (करोड़ रु॰)	अन्तर (प्रतिशत)	एनबीसी प्रतिशत के रूप में निर्यात ऋण
23 मार्च 2001	43321	10.7	9.3
28 मार्च 2008	129983	23.9	5.5
22 मार्च 2013	207618	14.2	3.9
21 मार्च 2014	229429	10.5	3.8

स्रोत: आरबीआई

टिप्पणी: एनबीसी = निवल बैंक ऋण
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में आंकड़ों में, आरबीआई से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरवी) के आंकड़ों को अलग रखा गया।

सारणी 7.9 : निर्यात ऋण

व्यापार नीति

नवीन व्यापार नीतिगत उपाय

7.29 18 अप्रैल 2013 को विदेशी व्यापार नीति में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई नीतिग कदम उठाए हैं। जो कि संघीय बजट 2013-14 में घोषित नीति और भारतीय रिजर्व बैंक की अपनी आर्थिक एवं क्रेडिट नीतियों में घोषित कदमों के अलावा हैं (बॉक्स 7.3)

बॉक्स 7.3 : हाल ही में कुछ चयनित नीतिगत उपाय

बजट सम्बन्धी

- चमड़े के निर्माण तथा चमड़े की वस्तुओं जिसमें फुटवियन भी सम्मिलित हैं, के लिए निर्धारित शुल्क को 7.5% से घटाकर 5% करना।
- अपरूप, कीमती तथा अर्ध कीमती पत्थरों पर शुल्क को 10% से घटाकर 2% करना।
- चावल की भूसी जिससे कि तेल निकाला जा चुका है, निर्यात शुल्क को वापिस लेना।
- वायुयान रखरखाव, मरम्मत तथा ओवरहॉल उद्योग को छूट।

जारी...

बॉक्स 7.3 : हाल ही में कुछ चयनित नीतिगत उपाय (जारी....)

- सिले हुए वस्त्र उद्योग के लिए, कॉटन के लिए फाइबर स्टेज पर शून्य उत्पाद शुल्क तथा मानवनिर्मित फाइबर से बने बटा सन के लिए फाइबर स्टेज पर 12% शुल्क। हस्तनिर्मित कार्पेट तथा जूट एवं कॉयर के कपड़े से निर्मित फर्श गलीचे को उत्पाद शुल्क से पूर्णत% छूट प्रदान की गई है।
- जहाज तथा पोत को उत्पाद शुल्क से छूट दी गई तथा आयातित जहाज तथा पोत पर कोई प्रतिकारी शुल्क न होना।

ऋण सम्बन्धी

- उच्च लागत सीमा, जिसको छ% माह से अधिक 200 आधार बिन्दु (बीपीएस) से संशोधित के बारे में 15 नवम्बर, 2011 को छ% से अधिक 350 आधार बिन्दु किया गया जो कि 30 जून 2014 तक लागू होगा।
- व्यापार ऋण का लाभ उठाने के लिए, व्यापार ऋण की अवधि को चालन प्राप्त तथा व्यापार लेन-देन से जोड़ा जाना चाहिए।
- साफ्टवेयर निर्यात या वस्तुओं को पूर्ण निर्यात को भारत में वापिस लाने तथा कार्यान्वयन के लिए बढ़े हुए समय को निर्यात की तारीख से 12 माह से कम करके 9 माह करना। विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में स्थित इकाइयों के कार्यान्वयन तथा भारत से निर्यात की तारीख से 12 माह के भीतर वस्तुओं/सॉफ्टवेयर/ सेवाओं के पूरे मान को वापिस लाया जाना चाहिए।

2013-14 में विदेशी व्यापार सम्बन्धी नितिगत उपाय

- इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए द रूपी एक्सपोर्ट क्रेडिट इंटरेस्ट एंड सबवेन्शन स्कीम को 101 टैरिफ लाइन तक बढ़ाया गया। इस योजना की वैध ता को भी 31 मार्च 2014 तक बढ़ाया गया। ब्याज आर्थिक सहायता की दर को भी 01.08.2013 तक 2% से बढ़ाकर 3% कर दिया गया।
- निर्यात के एफओबी मूल्य के 2% या 5% की दर पर डयूटी क्रेडिट के लिए लगभग 130 नए उत्पाद शामिल किए गए हैं। जिसमें इंजीनियरिंग, इलैक्ट्रॉनिक्स, रसायन, औषधि एवं वस्त्र उत्पाद शामिल हैं।
- मार्केट लिंक्ड फोकस प्रोडक्ट स्कीम (एमएलएफपीएस) के अंतर्गत लगभग 57 नए उत्पाद और दो नए देशों को सम्मिलित किया गया है। इन्क्रोमेहता स्पोर्टस इन्कन्वीजैशन स्कीम को वर्ष 2013-14 तक के लिए बढ़ा दिया गया है और इसमें 1.4.2013 से 53 लैटिन अमेरिकी तथा अफ्रीकी देशों को सूची में शामिल किया गया है।
- इन्क्रोमेहता स्पोर्टस इन्कन्वीमैशन स्कीम को वर्ष 2013-14 तक के लिए बढ़ा दिया गया है और इसमें 1.4.2013 से लेटिन अमेरिकी तथा अफ्रीका देशों की सूची में शामिल किया गया है।
- (एमएलएफपीएस) को संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोपीय संघ को किये जाने वाले निर्यात के उद्देश्य से 31 मार्च 2014 तक बढ़ा दिया गया है। जैसा अध्याय 61 तथा 62 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं (वस्त्र एवं परिधान) के मामले में किया गया है।
- फोकस प्रोडेक्ट स्कीम्स (एफपीएस) फोकस मार्केट स्कीम (एफएमएस) विशेष कृषि और ग्रामोद्योग योजना (पीकेजीयूआई) को स्क्रिप्स का सेवाकर के भुगतान में प्रयोग किया जा सकता है।
- दो नए शहरों को उत्कृष्ट निर्यात का शहर (टीआईआई) घोषित किया गया है। ये शहर हैं: गुडगांव (वस्त्र) और मोरबी (सिरामिक टाइल्स एवं सेनेट्री वेयर्स)
- 10/7/2013 को निर्यात के (एफओबी) मूल्य के 2% की दर से डयूटी क्रेडिट के लिए लगभग 160 नए उत्पाद शामिल किये गए हैं जिनमे 153 हाइटेक उत्पाद भी शामिल हैं (15/8/2013 से लागू)।
- मार्केट लिंक्ज धोकरन प्रोडक्ट स्कीम (एमएलएफपीएस) के तहत उत्पादों को शामिल किया गया है जिसमें 2% अतिरिक्त लाभ भी है।

राज्य-वार निर्यात संवर्धन के लिए नीति

7.30 निर्यातों का राज्य-वार प्रदर्शन (सारणी 7.10) शीर्ष पर गुजरात के बाद महाराष्ट्र के साथ केवल दो राज्यों का प्रभुत्व दर्शाता है। तमिलनाडु और कर्नाटक तीसरे और चौथे

सारणी 7.10 : शीर्ष भारतीय राज्यों का निर्यात प्रदर्शन

		मूल्य (मिलियन यूएस डॉलर)	हिस्सा			वृद्धि दर
		2013-14	2011-12	2012-13	2013-14	2013-14
1	गुजरात	73498	21.3	20.4	23.5	19.7
2	महाराष्ट्र	71661	22.4	22.1	22.9	7.9
3	तमिलनाडु	26937	9.1	9.0	8.6	-0.7
4	कर्नाटक	17821	5.1	5.8	5.7	1.7
5	आंध्र प्रदेश	15353	5.2	4.8	4.9	7.3
6	उत्तर प्रदेश	13309	3.5	3.6	4.3	21.6
7	हरियाणा	10657	3.0	3.2	3.4	9.2
8	पश्चिम बंगाल	10496	2.9	3.1	3.4	11.3
9	दिल्ली	9329	2.7	2.9	3.0	8.8
10	पंजाब	7063	1.9	2.2	2.3	8.8
11	राजस्थान	5915	2.2	2.3	1.9	-15.2
12	मध्य प्रदेश	4374	1.2	1.4	1.4	4.6
13	केरल	4285	2.7	3.2	1.4	-55.1
14	ओडिशा	4005	1.1	1.1	1.3	25.4
	कुल निर्यात	312610	100.0	100.0	100.0	4.1

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस

टिप्पणी: इसमें केवल वे राज्य शामिल हैं जिनका 2013-14 में भारत के निर्यात में कम से कम 1 प्रतिशत हिस्सा है।

स्थान पर हैं। 2013-14 में, लगभग 20 प्रतिशत की उच्च निर्यात वृद्धि दर के साथ गुजरात ने महाराष्ट्र को दूसरे स्थान पर धकेल दिया। अन्य राज्यों में, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा का निर्यात वृद्धि दो अंकों का था। केरल के निर्यात का हिस्सा 55 प्रतिशत की नकारात्मक निर्यात वृद्धि के कारण आधे से अधिक तक गिर गया। यह मुख्य रूप से मसाले के निर्यातों में गिरावट के कारण हुआ।

7.31 सारणी 7.10 में दिया गया राज्य-वार निर्यात केवल निर्देशात्मक है क्योंकि आंकड़े में कुछ दोष है। आंकड़ों को सीमाशुल्क से सूचना के अनुसार संकलित किया गया है और डीजीसीआईएंडएस की ओर से इसका कोई सत्यापन नहीं किया गया है। किसी एक शिपिंग बिल में निर्यातक द्वारा केवल एक उत्पत्ति का राज्य कूट दिया जा सकता है। एक राज्य से अधिक राज्यों से उत्पन्न होने वाली वस्तुओं को शामिल करते हुए बहु बीजकों वाले शिपिंग बिलों के मामले में, अलग-अलग प्रविष्टि करने का कोई प्रावधान नहीं है। सीमाशुल्क की दैनिक व्यापार विवरणी (डीटीआर) में उत्पत्ति के राज्य की गैर-रिपोर्टिंग काफी अधिक है और निर्यातकों की प्रवृत्ति वस्तुओं की उत्पत्ति के वास्तविक राज्य की बजाय उन विशेष वस्तुओं के लिए उत्पत्ति के राज्य के रूप में उन राज्यों की सूचना देने की है जिस राज्य से वे संबंधित हैं/जिस राज्य से बंदरगाह (जिसके माध्यम से निर्यात हुआ है) संबंधित है/जिस राज्य से उन्होंने वस्तुएं 'क्रय' की है। गैर-निर्माण निर्यातकों के मामले में समस्या और भी विकट है जो केवल क्रय के स्थान को जानते हैं न कि वस्तुओं के उत्पादन के स्थान को। आंकड़े की गुणवत्ता में सुधार के लिए इन दोषों को दूर किया जाना आवश्यक है।

7.32 केन्द्र सरकार राज्यों को निर्यात अवसंरचना विकास एवं संबद्ध गतिविधि (एएसआईडीई) योजना के लिए राज्यों को सहायता के माध्यम से निर्यात करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है जो राज्यों के निर्यात प्रदर्शन पर आधारित है। एएसआईडीई योजना के लिए परिव्यय में दो घटक हैं: राज्य घटक (कुल परिव्यय का 80 प्रतिशत) और केन्द्र घटक (कुल परिव्यय का 20 प्रतिशत)। वित्त वर्ष (2013-14) के लिए एएसआईडीई योजना हेतु 745.1 करोड़ रु॰ (संशोधित अनुमान) आवंटित किया गया है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र

7.33 फरवरी 2006 में एसईजेड अधिनियम और नियमावली अधिसूचित होने के बाद से लगभग आठ वर्षों की अवधि में 566 एसईजेड की स्थापना के लिए औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें से 388 को अधिसूचित किया गया है। वर्तमान में कुल 184 एसईजेड निर्यात कर रहे हैं। समग्र रूप से एसईजेड में 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार 12,83,309 व्यक्तियों के कुल रोजगार में से 11,48,605 व्यक्ति फरवरी 2006, जब एसईजेड अधिनियम लागू हुआ, के बाद सृजित वृद्धिशील रोजगार हैं। यह अवसंरचना निर्माण के लिए विकासकों द्वारा सृजित रोजगार के अतिरिक्त है। एसईजेड से वास्तविक निर्यात 2012-13 में 4,76,159 करोड़ रु॰ से बढ़कर रुपए के संदर्भ में 4.0 की वृद्धि दर्ज करते हुए 2013-14 में 4,94,077 करोड़ रु॰ तक हो गया है। 31 मार्च 2014 तक एसईजेड में कुल निवेश एसईजेड अधिनियम 2005 के बाद स्थापित नए अधिसूचित एसईजेड में 2,73,379 करोड़ रु॰ सहित लगभग 2,96,663 करोड़ रु॰ है। एसईजेड में, स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है।

प्रतिपाटन उपाय

7.34 2013 में, सभी देशों द्वारा 283 प्रतिपाटन जांच शुरू की गई जिसमें दोगुने से भी अधिक जांच शुरू करने के साथ ब्राजील ने भारत को पीछे छोड़ दिया (सारणी 7.11)। 2013 में, ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों आगे थे, जिन्होंने प्रतिपादन जांच शुरू करने में भारत को तीसरे स्थान पर धकेल दिया।

सारणी 7.11 : प्रतिपाटन उपाय 1995–2013 के शीर्ष दस उपयोगकर्ताओं द्वारा शुरू की गई जांच

		1995	2002	2004	2008	2011	2012	2013	1995-2013
1	ब्राजील	5	8	8	24	16	47	54	334
2	स. रा. अमरीका	14	35	26	16	15	11	39	508
3	भारत	6	81	21	55	19	21	29	702
4	ऑस्ट्रेलिया	5	16	9	6	18	12	20	267
5	अर्जेंटीना	27	10	12	19	7	13	19	312
6	कनाडा	11	5	11	3	2	11	17	183
7	इण्डोनेशिया	-	4	5	7	6	7	14	110
8	चीन	-	30	27	14	5	9	11	211
9	कोलंबिया	4		2	6	4	2	11	67
10	दक्षिण अफ्रीका	16	4	6	3	4	1	10	227
	सभी देश	157	311	220	218	165	209	283	4519

स्रोत: विश्व व्यापार संगठन

विश्व व्यापार संगठन वार्ता और भारत

7.35 3 से 7 दिसम्बर तक बाली, इंडोनेशिया में आयोजित विश्व व्यापार संगठन के नौवें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में एक संस्था के रूप में विश्व व्यापार संगठन की विश्वसनीयता सुदृढ़ हुई है। परिणाम ने यह सुनिश्चित किया कि विकास का पहलू दोहा दौर में ध्यान के केन्द्र में रहे। इसने विकासशील देशों के मध्य भारत की नेतृत्व भूमिका की पुन: पुष्टि की और वार्ता में इसकी रचनात्मक दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया। भारत ने करार को सफलता तक पहुंचाने और उसे आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत ने एक ऐसा परिणाम सुनिश्चित किया जो इसके सर्वोच्च राष्ट्रीय हित को सुरक्षित करता है। यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया गया कि कार्य लगे रहने के लिए पूरी तरह से तैयार रहते हुए भारत खाद्य सुरक्षा, आजीविका की सुरक्षा और इसके गरीबों के कल्याण से संबंधित मूलभूत मुद्दों पर कभी समझौता नहीं करेगा (बॉक्स 7.4)।

बॉक्स 7.4 : बाली में भारत और विश्व व्यापार संगठन सम्मेलन: मुख्य मुद्दे

व्यापार सुगमता (टीएफ)

बाली में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम देशों का टीएफ करार में शामिल होना था। अन्य समान विचारधारा वाले देशों के साथ भारत की लगातार कोशिश के परिणामस्वरूप अंतत: कार्यान्वयन कठिनाइयों के समाधान के लिए या तो वार्ता पाठ के अवांछित हिस्से का विलोपन हुआ या उसमें उपयुक्त बदलाव किया गया। बाली मंत्रिस्तरीय निर्णय ने एक ऐसा कार्य करने के लिए एक तैयारी समिति स्थापित किया जो टीएफ करार के शीघ्र लागू होने को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो। भारत ने करार के तहत अपेक्षित प्रतिबद्धताओं की श्रेणी पर भारत की अधिसूचना का मसौदा तैयार करने के लिए अंतर-मंत्रालयी परामर्श शुरू किया है।

खाद्य सुरक्षा के प्रयोजनार्थ सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग से संबंधित मंत्रिस्तरीय निर्णय

जी-33 (भारत सहित विश्व व्यापार संगठन में 46 विकासशील देशों का एक समूह) ने खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग हेतु निर्वाह करने वाले किसानों से खाद्यान्नों के क्रय के मुद्दे को बाली मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की कार्यसूची में लाने का निर्णय लिया। विश्व व्यापार संगठन में भारत की लगातार स्थिति यह रही है कि आजीविका, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास से संबंधित मामले अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। विकासशील देशों के लिए विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के तहत यथा प्रदत्त विशेष और विभेदात्मक व्यवहार आवश्यक है। यह संयुक्त राष्ट्र (यूएन) और खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) जैसे अन्य बहुपक्षीय मंचों में सदस्य राष्ट्रों की प्रतिबद्धता के भी पूर्ण अनुरूप है जहां गरीबी और भूख के खिलाफ लड़ाई को उच्च प्राथमिकता दी गई है। भारत ने इस बात पर जोर दिया कि कोई अंतरिम समाधान स्थायी समाधान नहीं हो सकता है और न ही इसे समाप्त किया जा सकता है जब तक कि बातचीत के जरिए कोई स्थायी समाधान न हो। यह स्पष्ट किया गया कि खाद्य सुरक्षा पर किसी संतोषजनक निर्णय के बिना भारत बाली पैकेज को क्षैतिज संतुलन रहित मानता है और इसलिए, इसका समर्थन करने में असमर्थ होगा। खाद्य सुरक्षा प्रस्ताव पर परिणाम ने व्यापार नियमों में कुछ असंतुलनों को दुरूस्त करना शुरू करने के लिए एक अवसर प्रदान किया है जो विश्व व्यापार संगठन में असंतुलनों की ऐतिहासिक विरासत के हिस्से हैं।

न्यूनतम विकसित देशों (एलडीसी) के लिए शुल्क मुक्त कोटा मुक्त बाजार पहुंच

दिसम्बर 2005 के हांगकांग मंत्रिस्तरीय घोषणा के तत्वों में से एक एलडीसी को शुल्क मुक्त कोटा मुक्त (डीएफक्यूएफ) पहुंच प्रदान करना था। इस मुद्दे पर दिसम्बर 2013 में बाली में मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में लिया गया मंत्रिस्तरीय निर्णय यह कहता है कि वे देश जिन्होंने उत्पादों के कम से कम 97 प्रतिशत के लिए इस प्रकार

जारी...

बॉक्स 7.4 : बाली में भारत और विश्व व्यापार संगठन सम्मेलन: मुख्य मुद्दे (जारी....)

की पहुंच प्रदान नहीं की है वे शामिल उत्पादों की संख्या में सुधार करेंगे। भारत एलडीसी को यह सुविधा प्रदान करने वाला पहला देश बना जब जब इसने 2008 में एलडीसी के लिए शुल्क मुक्त प्रशुल्क वरीयता (डीएफटीपी) योजना की घोषणा की। इस योजना की घोषणा एलडीसी को अपने व्यापार पहलों में सहयोग देने के लिए की गई और भारत की कुल प्रशुल्क लाइनों के लगभग 85 प्रतिशत पर शुल्क मुक्त पहुंच तथा प्रशुल्क लाइनों के लगभग 9 प्रतिशत पर वरीयता पहुंच प्रदान किया गया। केवल 6 प्रतिशत प्रशुल्क लाइनें अपवर्जन सूची में थे। इसके अलावा, 2005 के हांगकांग मिनिस्ट्रीयल मेंडेट के तहत प्रतिबद्धताओं के पूरा करने के साथ ही शुल्क युक्त सूची के अंतर्गत अतिरिक्त उत्पाद कवरेज के लिए कुछ एलडीसी के अनुरोध को पूरा करने और मूल प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लए सरकार ने पुरानी स्कीम का विस्तृत संस्करण प्रकाशित किया है। 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावी डीएफटीपी स्कीम भारत की 96.4% टेरिफ लाइनों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करती है और 2% लाइनों को जरजीही ड्यूटी का लाभ लेंगी। अपजर्वन सूची में, बिना शुल्क रियायत वाली महज 1.6% टेरिफ लाइनों को रिटेन किया हुआ है। नई विस्तारित स्कीम से उत्पत्ति संबंधी नियमावली के संदर्भ में कुछ प्रक्रियात्मक सरलीकरण भी होगा। वर्तमान में, 48 में से 31 एलडीसी इस योजना के लाभार्थी हैं। इनमें से, 21 लाभार्थी अफ्रीका से हैं।

द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग

7.36 अब तक, भारत ने 10 मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) और 5 वरीयता व्यापार समझौतों (पीटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं तथा ये एफटीए/पीटीए पहले से ही प्रभावी हैं। वर्तमान में, भारत 18 एफटीए पर वार्ता की प्रक्रिया में है (बॉक्स 7.5)।

बॉक्स 7.5 : भारत की क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्था: हाल के घटनाक्रम

भारत-ईयू द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश समझौता (बीटीआईए): वार्ता वस्तुओं, सेवाओं, निवेश, स्वच्छता और पादप-स्वच्छता उपाय, व्यापार के तकनीकी अवरोधों, व्यापार सुगमता और सीमाशुल्क सहयोग, प्रतिस्पर्धा, बौद्धिक सम्पदा अधिकारों (आईपीआर), और भौगोलिक संकेत (जीआई) के क्षेत्रों में जून 2007 में शुरू हुआ। अब तक वार्ता के पन्द्रह दौर और कई अंतर-सत्र तथा मुख्य मध्यस्थ-स्तरीय बैठकों का आयोजन किया गया है। ब्रूसेल्स में 15 अप्रैल 2013 को एक मंत्रिस्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।

भारत-आसियान व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए)-सेवा और निवेश समझौता: सेवाओं और निवेश पर समझौते पर वार्ता के निष्कर्षों की घोषणा 20 दिसम्बर 2012 को आसियान-भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में की गई। मंत्रिमंडल ने 19 दिसम्बर 2013 को समझौते को अनुमोदित और मंजूर किया। आसियान सचिवालय को समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर के लिए तारीख सूचित करने के लिए कहा गया है।

भारत-थाईलैंड सीईसीए: 82 मदों पर शीघ्र उपज योजना को कार्यान्वित किया गया। व्यापार वार्ता समिति (टीएनसी) का 29वां दौर 16-18 दिसम्बर 2013 को तय था किन्तु आंतरिक अशांति के कारण थाईलैंड द्वारा रद्द कर दिया गया। अगले दौर के लिए तारीख अभी तय किया जाना है।

भारत ईएफटीए बीटीआईए: यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के साथ इस द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश समझौता (बीटीआईए) का 13वां और अंतिम दौर 25-29 नवम्बर 2013 तक आयोजित किया गया। शामिल क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार, निवेश, आईपीआर, स्वच्छता और पादप-स्वच्छता उपाय, उत्पत्ति का नियम, व्यापार सुगमता और सीमाशुल्क सहयोग हैं।

भारत-न्यूजीलैंड एफटीए/सीईसीए: वार्ता का नौवां दौर 29-30 जुलाई 2013 को वेलिंगटन, न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया जिसके बाद नई दिल्ली में 9-10 दिसम्बर 2013 को अंतर-सत्र चर्चा की गई। शामिल क्षेत्रों में वस्तुएं, सेवाएं, निवेश और संबंधित मुद्दे हैं।

भारत-इजराइल एफटीए: वार्ता का आठवां दौर इजराइल में 24-26 नवम्बर 2013 तक आयोजित किया गया। शामिल क्षेत्रों में वस्तुओं में व्याार, उत्तपत्ति के नियम, सीमाशुल्क प्रक्रिया और प्राकृतिक व्यक्तियों का आवागमन शामिल हैं।

भारत-चिले पीटीए: पीटीए के विस्तार पर चर्चा करने के लिए अब तक, पांच संयुक्त प्रशासन समिति बैठकों/वार्ता का दौर आयोजित किया गया है। भारत चिले पीटीए के मुद्दे पर चर्चा के लिए दोनों देशों के बीच अधिकारी स्तर की बैठक फरवरी 2014 में आयोजित की गई। शामिल क्षेत्रों में वस्तुओं में व्यापार, उत्तपत्ति के नियम, एसपीएस और टीबीटी हैं।

भारत-कनाडा एफटीए: जून 2013 में ओटावा, कनाडा में आठवां दौर आयोजित किया गया। अगला दौर नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। शामिल क्षेत्रों में वस्तुओं में व्यापार, सेवाओं में व्यापार, उत्पत्ति के नियम, एसपीएस और टीबीटी हैं।

भारत-ऑस्ट्रेलिया एफटीए/सीईसीए: अब तक वार्ता के पांच दौर आयोजित किए गए हैं। पांचवां दौर मई 2013 में केनबरा, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। शामिल क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार, निवेश और आईपीआर से संबंधित मुद्दें हैं।

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) समझौता: आरसीईपी समझौता आसियान + छह एफटीए सहयोगियों (ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड) के बीच है% नवम्बर 2012 में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं की घोषणा के आधार पर 10 आसियान राष्ट्रों और इसके छह एफटीए सहयोगियों के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी के लिए वार्ता मई 2013 में शुरू हुआ। चौथा दौर 31 मार्च से 4 अप्रैल 2014 तक नैनिंग, चीन में आयोजित किया गया। वार्ता का अगला दौर 22-27 जून, 2014 तक सिंगापुर में नियत है।

चुनौतियां एवं संभावनाएं

चुनौतियां

भारत के निर्यात को अगले पांच वर्षों में विश्व निर्यातों में कम से कम 4 प्रतिशत हिस्से के सम्मानित अनुमानित आंकड़े तक पहुंचने के लिए वार्षिक रूप से लगभग 30 प्रतिशत तक निरंतर बढ़ना चाहिए।

7.37 विश्व निर्यात में भारत के व्यापारिक माल के निर्यात का हिस्सा 1990 (जिसके बाद भारत में आर्थिक सुधार शुरू किया गया) में 0.5 प्रतिशत से 2013 में केवल 1.7 प्रतिशत तक बढ़ा, जबकि उसी अवधि के दौरान चीन का हिस्सा 1.8 प्रतिशत से 11.8 प्रतिशत तक बढ़ा। इस प्रकार विश्व व्यापारिक माल के निर्यातों के हिस्से में भारत और चीन के बीच चौड़ी खाई है। यह अंतर सेवा निर्यातों में कम है (चित्र 7.2)।

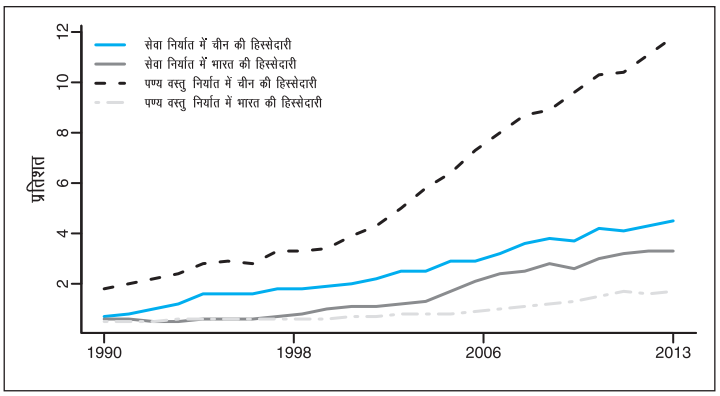

चित्र 7.2 : विश्व में निर्यात हिस्सा: भारत और चीन की तुलना

7.38 भारत को विश्व व्यापारिक माल के निर्यातों के इसके हिस्से को 2013 में 1.7 प्रतिशत से अगले पांच वर्षों में कम से कम 4 प्रतिशत के सम्मानित अनुमानित आंकड़े तक बढ़ाने का लक्ष्य रखना चाहिए जिसके लिए निर्यातों को लगभग 30 प्रतिशत के सीएजीआर तक बढ़ना चाहिए। यह असंभव नहीं है, क्योंकि 2003-04 से 2007-2008 के दौरान, भारत का निर्यात 2 वर्ष में 29 और 31% की विकास दर से 20% वार्षिक दर से अधिक दर से निरन्तर बढ़ा। इसे मीडियम अवधि में प्राप्त करना, एक बड़ी चुनौती है जिसके लिए कुद आसाधारण कदम उठाए, एक बड़ी चुनौती है जिसके लिए कुछ आधारभूत कदम उठाए जाने की आवश्यकता है जैसे उत्पाद विविध ता, निर्यात आधारभूत संरचना तैयार करना, उपयोगी एफ॰टी॰ए॰/क्षेत्रीय व्यापार करार पर केन्द्रित होना व्युतक्रमी कर संरचना का निवारण, निर्यात पदोन्नति योजनाओं को युक्तियुक्त बनाना और व्यापार को सुकर बनाने के लिए कदम उठाना। (बॉक्स 7.6)

बाक्स 7.6 : भारत के जिंस व्यापार क्षेत्र में कुछ मुख्य मुद्दे

भारत के निर्यात क्षेत्र को विश्व निर्यात के हिस्से के मामले में अभी आगे बढ़ाना है, तथापि अलग-अलग समय में इसका उच्च विकास हुआ है। इस क्षेत्र के कुछ मुख्य मुद्दे निम्नलिखित है।

उत्पाद विविधता:- जबकि भारतीय निर्यात बास्केट में बाजार विविधता और संरचना परिवर्तन रहे हैं, लेकिन मांग आधारित उत्पाद विधिता नहीं हुई है। वर्ष 2013 में चार अंकीय एच॰एच॰ स्तर पर विश्व के 100 मुख्य आयातों में भारत की केवल 5 मद्दे थी तथा इनका हिस्सा 5% और इससे अधिक था। इसके बावजूद हीरा (21.0%) और आभूषण की मद्दें (11.2%) जिनको दोहरे अंक का हिस्सा था, की छोड़कर, अन्य तीन मदों का हिस्सा केवल 6-7% था। विश्व की आयात की 100 मुख्य मदों में तीन-ई, आयात, इलैक्ट्रानिक, इलैक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग मदें- और कुल वस्त्र की मदें शामिल थीं। यद्यपि हाल ही के वर्षों में इंजीनियरिंग वस्तुओं की संख्या में बढ़ोतरी एक सकारात्मक चिन्ह है, भारत अन्य प्रतियोगी देशों से बहुत पीछे है। इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर क्षेत्र को विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है जो कि भारत द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी करार पर हस्ताक्षर करते समय, जो वास्तविक रूप से उस समय डगमगा गया था जो भारत का सेमीकन्डकटर क्षेत्र विकास की आरम्भिक अवस्था में था, जबकि नए औद्योगिक देशों और विकसित देशों ने पहले ही यह कर लिया था। अभी तक हमारा केन्द्र बिन्दु उस निर्यात पर था, जो हम कर सकते हैं (अथवा आपूर्ति आधारित), अब हमें उन मदों की है ओर अंतरित होना है जिनके लिए विश्व की मांग है तथा हमारे पास उसकी आधार भूत क्षमता है। मांग आधारित निर्यात बास्केट विविधता दृष्टिकोण तथा तीन ई-के प्रति अन्तरण से, भारत को अधिक लाभांश प्राप्त होगा।

निर्यात आधारभूत संरचना:- निर्यात आधार भूत संरचना, विशेषकर बन्दरगाहों से संबंधित आधारभूत संरचना, जो व्यापार को प्रभावित करती है, पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। हालांकि हमारे सर्वोत्तम बन्दरगाहों में स्टेट ऑफ आर्ट-प्रौद्योगिकी नहीं है जैसाकि सिंगापुर, रोटरडम और शंघाई में है। बन्दरगाह

जारी.....

बाक्स 7.6 : भारत के जिंस व्यापार क्षेत्र में कुछ मुख्य मुद्दे (*जारी....)*

आधारभूत संरचना मुद्दोंमें शामिल हैं सड़क की खराब हालत और बन्दरगाह से इसका जुड़ा होना, जाम, वैसल बर्थिंग में देरी, कारगो के रखरखाव की तकनीक और उपस्कर की दयनीय स्थिति, कंटेनीकृत कारगो की पहुंच की कमी, तथा बार-बार ई०डी०आई० सर्वर का डाऊन होना अथवा रखरखाव जिससे कई दौर से गुजरना पड़ता है, लीड समय में बढ़ोतरी होती है, विनिमय लागत बढ़ती है तथा बाजार की प्रतियोगिता से परे होना पड़ता है। निर्यात आधारभूत संरचना, युद्ध स्तर पर तैयार की जाए। जैसेकि भारत के हवाई अड्डों और मैट्रोरेल में तेजी से बड़े परिवर्तन लाए गए हैं, उसी प्रकार समुद्री बन्दरगाहों को प्राथमिकता दी जाए।

उपयोगी क्षेत्रीय व्यापार ब्लाक पर ध्यान देना:-भारत के कुछ एफ०टी०ए०/आर०टी०ए०/सी०ई०ए० के कारण व्युतक्रम शुल्क संरचना जैसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें कुछ फिनिशड वस्तुओं पर आयात शुल्क शून्य है अथवा अन्य देशों में आयात की जाने वाली कच्ची सामग्री पर लगने वाले शुल्क से कम है अथवा अन्य देशों से आयात की जाने वाली कच्ची सामग्री पर लगने वाले शुल्क से कम है। इसके अलावा घरेलू क्षेत्र, जोकि जीविका से जुड़ा है, वह भी उपर्युक्त से प्रभावित हुआ है। भारत को क्षेत्रीय और द्विपक्षीय करारों की तरफ झुकाव के कारण अर्थपूर्ण और परिणामोन्मुखी एफ०टी०ए०/आर०टी०ए०/सी०ई०ए० होने चाहिए। अत% ऐसी मदें, जिनके लिए शुल्क में रियायत दी गई है तथा घरेलू उत्पादन पर पड़ने वाले उनके प्रभाव, के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करके मौजूदा आर०टी०ए०/एफ०टी०ए०/सी०ई०ए० की वास्तविक जांच-पड़ताल किए जाने की आवश्यकता है। भारत की, यू०एस० ई०यू० के बीच टी०ए०एफ०टी०ए० जैसे नए खतरों, जो विश्व का सबसे बड़ा मुक्तव्यापार क्षेत्र, निवेश का संरक्षण और अनावश्यक विनियामक बाधाओं को हटाता है, का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी बीच कुछ नए उपयोगी आर०टी०ए०/एफ०टी०ए०/सी०ई०एफ०ए० की भी आवश्यकता है जिनके लिए वार्ता पहले ही शुरू कर दी गई है पणधारियों की और भागेदारी, मनमुटाव को कम करने में मदद कर सकती है।

इनवरटिड शुल्क संरचना:-इनवरटिड शुल्क संरचना भारतीय निर्मित वस्तुओं को, घरेलू बाजार में फिनिशड उत्पाद आयातों के मुकाबले अप्रतियोगी बना रही है क्योंकि फिनिशड वस्तुओं पर, कच्चे सामग्री अथवा माध्यस्थ उत्पादों की तुलना में कम दरों पर कर लगाया जाता है। इससे घरेलू मूल्य एडिशन हतोत्साहित होता है। यह इनवर्शन ने केवल आधारभूत सीमा शुल्क के कारण है, अपितु, अन्य अतिरिक्त करों के लिए भी। जापान और दक्षिण कोरिया और एशियन जैसे देशों के साथ क्षेत्रीय/द्विपक्षीय एफ०टी०ए० से, इन सांझेदार देशों के साथ शून्य अथवा कम शुल्क वाली अन्तिम वस्तुओं के संबंध एक नई इनवर्टड शुल्क जैसी स्थिति पैदा हो गई है जबकि अन्य देशों से इन मदों की सामग्री के लिए उच्च शुल्क है। इन्वर्टड शुल्क, अलग-अलग क्षेत्रों में लगाया जाता है। इससे बचा जाना चाहिए तथा विभिन्न पणधारियों के बीच सही संतुलन होना चाहिए।

निर्यात संवर्धन योजनाएं:- मल्टीपल और ओवरलैपिंग निर्यात संवर्धन योजनाएं हैं जिसके केन्द्र बिन्दु के कई बाजार था कई उत्पाद है तथा विदेश व्यापार नीति में प्रत्येक वर्ष कई बाजार शामिल हो रहे हैं। एक बात जो व्यापार नीति उपायों की लघु चुनिन्दा सूची से भी स्पष्ट दिखाई देती है, (बाक्स 7.3) वह है योजनाओं और रियायतों की बाहुल्यता, जो आवधिक रूप से बढ़ती जा रही है। निर्यात संवर्धन योजनाओं को न्यूनतम करने के लिए क्रम में युक्तियुक्त बनाने की आवश्यकता है जिससे विनिमय लागत और व्यापार मुकदमेंबाजी कम हो जाएगी। रियायत की काफी अधिक दरें भी नहीं होनी चाहिए। ड्यूटी प्रतिअदायगी योजना के लिए, एक ही तरह की मदों के संबंध में अलग-अलग दरों के स्थान पर सीमित दरें होनी चाहिए। इससे चीजें सरल हो जाएंगी तथा विवेकाधीन निर्णयों से बचा जा सकेगा। जहां कहीं टैरिफ कम हैं या जिन्हें कम किया जा सकताहै, वहां निर्यात प्रोत्साहन वापस ले लिए जाएं क्योंकि शुल्क में रियायतों के कारण लेन देन लागत, प्रसुविधाओं से अधिक हो सकती है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र:- भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) के लिए स्पष्ट संकेत दिए जाने की आवश्यकता है क्योंकि हाल ही के वर्षों में नया निवेश मंद हो गया है तथा ग्रीन फील्ड सेज अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हुए हैं। जबकि नए उत्पादन क्षेत्रों की योजना बनाई जा रही है, सेज में बहत सा निवेश पहले ही किया जा चुका है जिसकी पूरी क्षमता का दोहन अभी किया जाना है। ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां सेज की हालत घरेलू टैरिफ क्षेत्र एककों से भी खराब है, जैसाकि एफ०टी०ए० रियायतों को लागू नहीं किए जाने के मामले में जब सेज, डी०टी०ए० में बिक्री करते हैं।

व्यापार को सुकर बनाना:- आधारभूत अड़चनों के अतिरिक्त, प्रक्रियात्मक और दस्तावेजी कारकों के कारण विलंब और उच्च लागत को कम करते हुए व्यापार को सुविधा जनक बनाना एक और बड़ी चुनौती है। विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के प्रकाशन ''डूईंग बिजनेस 2014'' के अनुसार व्यापार के मामले में भारत का 134वां स्थान है जबकि सिंगापुर का प्रथम और चीन 96वें स्थान पर है। सीमापार व्यापार में भारत का 132, सिंगापुर का प्रथम और चीन का 74वां स्थान है। भारत को सिंगापुर के तीन और चीन के 8 दस्तावेजों के मुकाबले भारत को 9 निर्यात दस्तावेजों की आवश्यकता है। निर्यात करने का समय भारत में 16 दिन तथा सिंगापुर में 6 दिन है। भारत के 20 तथा सिंगापुर के लिए 4 आयात दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। प्रतिकन्टेनर लागत, भारत में 1170 यू०एस० डालर, सिंगापुर में 460 यू०एस० डालर, चीन में 620 यू०एस० डालर और भारत को प्रति कन्टेनर आयात लागत 1250 अमरीकी डालर, सिंगापुर में 440 अमरीकी डालर, और चीन में 615 यू०एस० अमरीकी डालर है। इसके अलावा अन्तर-मंत्रालयी विलंब भी होता है। संबंधित मंत्रालयों का एकीकरण करने की मौजूदा पहल सही दिशामें एक कदम है, यद्यपि इसमें बहुत कुछ और किया जाना है। नीति घोषणा और अधिसूचना का जारी किया जाना, साथ-साथ होना चाहिए।

घरेलू और विदेश क्षेत्र नीति को आयात से जोड़ना:- जबकि एक स्थिर कृषि निर्यात नीति की आवश्यकता है, कोई भी घरेलू कमी अथवा अधिकता, निर्यात को प्रभावित करती है। इसी प्रकार बाह्य कमी/अधिकता, घरेलू क्षेत्र को प्रभावित करती है। अत% विशेषत% कृषि के लिए घरेलू और बाह्य-क्षेत्र की नीतियों को कारगर तरीके से, जोड़ने की आवश्यकता है। मुख्य बेमेल को समाप्त करने के लिए अग्रिम आर्थिक और बाजार आसूचना भी आवश्यक है।

यदि इन मुद्दों का निवारण किया जाता है तो इससे भारत के निर्यात में अत्यधिक लाभ होगा।

स्रोत: डा०एच०एस०सी० प्रसाद, डा० आर० सतीश, और सलाम श्याम सुन्दर, भारतीय मर्केन्डाइज निर्यात पर आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय वर्किंग दस्तावेज पर आधारित: कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे और नीतिगत सुझाव।

संभावनाएं

7.39 आई०एम०एफ० को अप्रैल, 2014 के विश्व आर्थिक आऊटलुक ने यह संभावना व्यक्त की है कि विश्व व्यापार 2013 के 3.0% के मुकाबले वर्ष 2014 में 4.3% तथा 2015 में 5.3% हो जाएगा तथा जो एडवान्स देशों के निर्यात और आयात विकास में संवर्धन को दर्शाता है। तथापि वास्तविक आधार की तस्वीर सकारात्मक नहीं है क्योंक बाल्टिक ड्राई सूचकांक, जोकि विश्व व्यापार के बढ़ने का अच्छा सूचक है, लाल निशान पर है। यह वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट से निम्नतम चरणों में है तथा यह मई 2008 के 11793 के शीर्ष के मुकाबले 14 अप्रैल, 2014 से अधिकांश दिन 1000 सूचकांक से कम पर रहा। (चित्र 7.3) पांच मांह के कम/नकारात्मक विकास के पश्चात् अप्रैल-मई, 2014 में, भारत के निर्यात में वृद्धि यद्यपि एक सकारात्मक चिन्ह है, अपितु यह आंशिक रूप से निम्न आधार के कारण हैं।

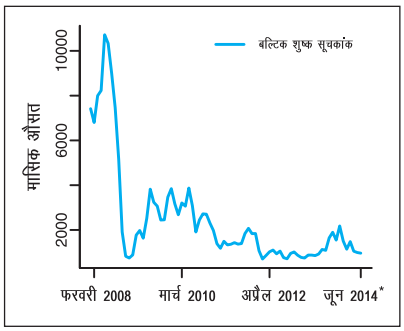

चित्र 7.3 : बाल्टिक ड्राई सूचकांक (मासिक औसत)

7.40 विश्व और मुख्य व्यापारिक देशों की निर्यात और आयात का त्रैमासिक और मासिक कार्य-निष्पादन, प्रोत्साहित करने वाला नहीं है। अच्छे विश्व की 2013 का क्यू-3 और क्यू-4 का निर्यात और आयात विकास जारी नहीं रहा। क्यू 1 2014 में यह पिछली तिमाही को 4.3% तथा 2.1% से कम होकर क्रमश% 1.8% तथा 1.9% हो गया। ई०यू० और सिंगापुर को छोड़कर, सभी महत्वपूर्ण देशों का 2014 क्यू 1 निर्यात विकास या तो नकारात्मक है अथवा न्यून है। आयात विकास के मामले में भी, जो भारत सहित अन्य देशों के निर्यात की योग को दर्शाती है, स्थिति बिल्कुल एम समान है। अप्रैल और मई, 2014 के लिए कुछ देशों के लिए उपलब्ध मासिक आयात विकास दर में भी कोई सुधार नहीं है। अत% विश्व व्यापार और भारत का निर्यात हाल ही के अच्छे कार्य-निष्पादन की अनदेखी करते हुए अभी भी अस्थिर है। यह इराक संकट के कारण तेल की बढ़ी कीमतों के बाहरी दबाव के कारण भी उाऊन साइड जोखिम है।

जबकि जिंस विश्व व्यापार और भारत का निर्यात हाल ही के अच्छे कार्य निष्पादन को देखते हुए अभी भी अस्थिर है, भारत के सेवा निर्यात के संकेत मिले-जुले हैं।

7.41 सेवाओं का विकास काफी हद तक वैश्विक विकास और व्यापार पर निर्भर करता है। बाल्टिक ड्राई सूचकांक का गिरता स्तर, शिपिंग, परिवहन, बन्दरगाह और बीमा तथा संबद्ध सेवाओं में दिखाई देगा। आई०टी० सेवाओं का भविष्य तथापि अच्छा दिखाई देता है जहां गार्नर, 2014 में आई०टी० विश्व-वार खर्च में 3.1% बढ़ोतरी दिखा रहा है तथा एन०ए०एस०एम०/सी०ओ०एम० वर्ष 2014 में भारत आई०टी० कारोबार प्रक्रिया प्रबंधन सेवा में 13-15% का विकास दर्शा रहा है। विदेशी पर्यटकों के भारत में आने की 10.6% की अच्छी दर तथा वर्ष 2014-15 के प्रथम दो माह में विदेशी मुद्रा का 11.4% विकास, भारतीय पर्यटन क्षेत्र के लिए अच्छा है। अत% भारत के सेवा निर्याप्त के संकेत मिले-जुले हैं।